Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, NOV-DEC, 2018, VOL- 6/48

भारत में विकास योजनाओं का महत्व

सुबोध कुमार अग्रवाल, Ph. D.

बी0 एस0 ए0 कालेज, मथुरा

Abstract

ऋग्वेद, महाभारत काल, स्मृतिकाल एवं विभिन्न कालों की संहिताओं में ग्रामीण जीवन का वृहद विवेचन किया गया है। ग्रामीण भारत की समस्याओं एवं जनमानस के मध्य व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए सदैव से ही प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्राम व बस्तियों को सड़क मार्गों से जोड़ना, इन्दिरा आवास योजना, स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना, भूमि सुधार योजना, मनरेगा, ट्राईसेम, आशा योजना, पल्स पोलियो कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास के तहत ऑगनबाड़ी–बालबाड़ी कार्यक्रम, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा कार्यक्रम, मिड–डे–मील कार्यक्रम, जन स्वास्थ्य व स्वच्छता कार्यक्रम, मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम, पों" ाहार कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जलापूर्ति एवं वातावरण स्वच्छता कार्यक्रम, अम्बेडकर ग्राम विकास कार्यक्रम, कॉसीराम मालिकाना हक योजना, कॉसीराम मलिन बस्ति आवास योजना आदि विकास कार्यक्रम स्थानीय स्तरों पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

पारिभाषिक शब्दावली: *ग्रामीण जीवन, ग्रामीण भारत की समस्यायें, विकास योजना, राष्ट्र विकास।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शोध प्ररचना : शोध अध्ययन को सम्पादित करने के लिए पूर्णतः द्वितीयक तथ्यों पर आधारित वर्णनात्मक शोध प्ररचना को चुना है, जिसमें ऐतिहासिक अध्ययन पध्दति को भी समावेशित किया गया है, ताकि अध्ययन की प्रस्तुति सरल किन्तु तार्किक रूप में की जा सके।

विवेचना: वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन भले ही बाद की घटना हो, लेकिन भारत की सम्पूर्ण संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक मूल्यों में प्राचीन काल से ही ग्रामीण विकास के चिन्तन का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। ऋग्वेद, महाभारत काल, स्मृतिकाल एवं विभिन्न कालों की संहिताओं में ग्रामीण जीवन का वृहद विवेचन किया गया है। ग्रामीण भारत की समस्याओं एवं जनमानस के मध्य व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए सदैव से ही प्रयास किए गए हैं। वैज्ञानिक अध्ययन और विकास के लिए सभी विकासशील राष्ट्रों द्वारा विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए **''आर्थिक नियोजन''** को विशेष महत्व दिया गया है। हमारे देश में भी प्राचीन काल से ही गरीबी को

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

दूर करने के लिए **''आर्थिक नियोजन''** पर विशेष ध्यानाकर्षण किया गया है किन्तु फिर भी विभिन्न समस्याओं के कारण यथोचित सफलताएँ एवं उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हो सकों है।

भारत में विकास–योजनाओं को मुख्यतः दो भागों में बॉटा जा सकता है।

1– स्वतंत्रता–प्राप्ति से पूर्व की योजनायें।

2– स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् की विकास योजनायें।

सामान्यतः भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत सामाजिक जीवन के कछ पक्षों का अध्ययन 19वीं शताब्दी से आरम्भ हुआ। एक विशेष बात यह है कि ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण समस्याओं अथवा ग्रामीण विषयों के अध्ययन का मुख्य उददेश्य ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण करना अथवा एक सुधारबादी दृष्टिकोण को लेकर चलना नहीं था बल्कि ऐसे अध्ययनों का उदेद्श्य केवल राजनैतिक लाभ प्राप्त करना ही था। इसके पश्चात् भी 19वीं शताब्दी के आरम्भ में जो ग्रामीण अध्ययन किये गये, उन्होंने कुछ ऐसे प्रतिमानों को विकसित किया जो भारतीय विद्वानों के लिए बाद में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए।

भारत में 20वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित जितने भी आनुभविक अथवा सैद्धान्तिक अध्ययन किये गये, वे अर्थशास्त्रियों के प्रयासों के ही परिणाम थे। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में इन आनुभविक अध्ययनों का ऐतिहासिक महत्व होते हुए भी इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का वास्तविक आधार नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये सभी पूर्व अध्ययन सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले थे।

अनेक अर्थशास्त्रियों एवं समाज वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए विभिन्न क्षेत्रीय अध्ययनों से आर्थिक नियोजन हेतु एक दिशा मिली। परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण प्रयास सन् 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस दल द्वारा दिल्ली में सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में किया गया। इस दल द्वारा देश को हीन आर्थिक दशा, गरीबी तथा बेकारी के निवारण के लिए औद्योगीकरण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। परिणामस्वरूप देश की आर्थिक समस्याओं के अध्ययन् एवं निराकरण के लिए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु **''राष्ट्रीय योजना समिति'' की स्थापना पं0 नेहरू की अध्यक्षता में की**

गई। इस समिति के प्रयासों से जनता में जागृति पैदा हुई। अतः 4 जुलाई, 1944 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता के भारी दबाव के कारण **''सर अर्देशियर दलाल'' के नेतृत्व में ''नियोजन एवं विकास विभाग'' की स्थापना की गई।** इस विभाग को विकास योजनाएं निर्मित करने का कार्यभार सौंपा गया। इस विभाग द्वारा निर्मित विकास योजनाएं मात्र कागजा तथा दफ्तरों तक ही सीमित रहीं। तत्पश्चात् **श्री के0 सी0 वियोगी की अध्यक्षता में सन् 1946 में एक ''नियोजन सलाहकार समिति'' गठित की गई।** इस समिति का कार्य, उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के लिए आर्थिक नीति निर्धारित करना, औद्योगीकरण के लिए विभिन्न उद्योगों के विकास हेतु समितियॉ गठित करना, बेरोजगारी को दूर करने के लिये योजनायें बनाना, जीवन स्तर उठाने व आर्थिक सम्पन्नता के लिए उपलब्ध साधनों के अधिकतम एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देना था। इस प्रकार विभिन्न सूत्रों द्वारा भारत में आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु निम्नाकित विभिन्न विकास योजनाऐं प्रस्तुत की गईं।

1– बम्बई योजना :– भारतीय सन्दर्भ में सन् 1944 में देश के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने एक पन्द्रह वर्षीय विकास योजना **''ए प्लान फॉर इकोनोमिक डबलपमेन्ट''** प्रस्तुत की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तिगुनी तथा प्रति व्यक्ति आय में दुगुनी वृद्धि करना तथा प्रति व्यक्ति 2600 कैलोरी आहार, प्रति वर्ष 30 गज वस्त्र तथा आवास के लिए 100 वर्गफुट आकार के आवास गृह की व्यवस्था करना था।

2– जनवादी योजना :– भारत में सन् 1944 में एम.एन. राय की अध्यक्षता में **''जनवादी योजना''** प्रस्तुत की गयी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :–

(I) उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना।

(II) कृषि एवं कुटीर – उद्योगों को बढ़ावा देना।

(III) सन्तुलित आहार, वस्त्र, चिकित्सा आवास, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना।

3– गॉधीवादी योजना :– यह योजना गॉधी जी के चिन्तन परम्परा को साकार रूप देने पर आधारित की गयी। इसके अन्तर्गत साधारण जीवन–यापन, अहिंसा, श्रम तथा मानव–मूल्य चार प्रमुख अंग रखे गये। इस योजना का प्रत्यक्ष प्रभाव अपने देश में निर्मित

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

की जाने वाली अग्रिम आर्थिक विकास योजनाओं, कृषि, कुटीर–उद्योगों, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था और सामाजिक अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी क्षेत्रों पर विशेष रूप से पड़ा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् की विभिन्न विकास योजना :– भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ग्रामीण अध्ययनों के प्रति बढ़ती हुई रूचि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को एक नई दिशा प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के कुछ वर्ष पहलें महात्मा गॉधी ने ''**गॉव को वापस चलो**'' का जो नारा दिया था। उसे साकार करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के प्रति अपना ध्यान केन्द्रित किया। इस प्रयास के अन्तर्गत ग्रामीण जीवन का अध्ययन करने के लिए न केवल विशेष शोध समितियॉ गठित की गई बल्कि ग्रामों के चतुर्दिक विकास को अपना प्राथमिक लक्ष्य मानते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भी व्यापक स्तर पर लागू किया जाने लगा। योजना आयोग का गठन होने के पश्चात् इसी आयोग से सम्बद्ध एक ''**कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन**'' की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य भारत जैसे आर्थिक, भौगोलिक और सॉस्कृतिक विविधता से युक्त देश के लिए प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कराना तथा विभिन्न विकास योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करना था। **डॉ0 देसाई के शब्दों में ''स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकार्य एवं विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन केवल आवश्यक ही नहीं था अपितु यह अनिवार्य भी हो गया था।''** इस संदर्भ में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सरकार के सभी प्रयत्नों से भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत के बुद्धिजीवियों का ध्यान ग्रामीण जीवन की ओर आकर्षित हुआ जिसके फलस्वरूप ग्रामीण विकास में व्यापक रूचि ली जाने लगी।

अतः 15 अगस्त, 1947 को विदेशी दासता से छुटकारा प्राप्त कर देश में विकास की विभिन्न योजनाओं तथा तत्सम्बन्धित समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के विशेष प्रयत्न किए गए। इन विषम परिस्थितियों तथा समस्याओं के कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी तथा भुखमरी का निराकरण करना राष्ट्रीय सरकार का मुख्य कर्तव्य तथा लक्ष्य बन जाने के कारण ''**आर्थिक विकास की नीतियों का निर्धारण करना**'' प्रारम्भ हुआ। विकास योजनाओं के प्रथम चरण में 1 जनवरी, सन् 1948 को ''**कोलम्बो योजना**'' की स्थापना की गई तथा 6 अप्रैल, सन् 1948 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

एक औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस औद्योगिक नीति में निजी तथा सार्वजनिक उद्योगों के विकास, सार्वजनिक हितों की दृष्टि से निजी क्षेत्र के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया। सन् 1948–1949 में ग्रामीण समस्याओं हेतु वित्तीय एवं भूमि सुधार सम्बन्धी नीतियों का भी प्रावधान किया गया। स्वतंत्र भारत का नया संविधान लागू होने के पश्चात् श्री जय प्रकाश के प्रयत्नों से 30 जनवरी, 1950 को **''सर्वोदय योजना''** सामाजिक क्रान्ति के निश्चित कार्यक्रम के रूप में आर्थिक विकास के लिए लागू की गई।

शोध परिलब्धि :

1. विकास कार्यक्रमों (यथा : जननी सुरक्षा कार्यक्रम (आशा), मनरेगा, पल्स पोलियो, मिड–डे–मील) ने ग्रामीण महिलाआ को रोजगारों के अवसर सुलभ कराए हैं।''
2. विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, ' ोक्षिक तथा राजनीतिक प्रस्थितियों में रचनात्मक भूमिकाएं निर्वाह की हैं।''
3. ''संवैधानिक प्रावधानों ने अधिकांशतः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन म महिलाओं की सहभागिता व क्रियाशीलता को सुनिश्चित तथा प्रोत्साहित किया है।''
4. विकास कार्यक्रमों ने घर में कैद ग्रामीण महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकाल कर अर्थोपार्जन करके परिवार को आर्थिक मदद करने हेतु प्रोत्साहित किया है।
5. विकास कार्यों में ग्रामीण महिलाओं में सवर्ण जाति से पिछड़ी जातियों तथा पिछड़ी जाति से अनुसूचित जातियों की महिलाओं में जागरूकता व सहभागिता तुलनात्मक अधिक पायी गयी है।''
6. ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत रोड्स तथा लिंग रोड्स बन जाने से ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक– राजनीतिक क्रियाशीलता में वृद्धि हुई है।''
7. विकास कार्यक्रमों ने मजदूरों के ग्राम–नगर पलायन में कमी की है।''
8. विकास कार्यक्रमों के प्रति ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता जनित करने में 'जन संचार साधनों' में दूरदर्शन में अहम भूमिका निर्वाह की है।''
9. विकास कार्यक्रम; ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।''

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सन्दर्भ ग्रन्थ :–

''योजना'' – पत्रिका, *सरकारी प्रकाशन, नई दिल्ली, नवम्बर 1985 पेज – 22*
दैनिक समाचार पत्र – ''अमर उजाला'' *23 सितम्बर, 1985 पेज – 3*
Ojha, B.L.: *- The Ecomonic Policy in India the College Book Report & Publishers, Jaipur, (Rajasthan) 1969 Page – 11*
Vidyarthi L.P., *Rise of Development in India : The Rural – Urban and Other Dimensions, Vol. – 11 (1978) Page – 13*

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies